Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

अगस्त (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- आयरन ओर ब्लॉक नीलामी में राजस्थान ने रचा नया इतिहास 3
- भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को किया सम्मानित 3
- राजस्थान में 'लंपी' वायरस प्रभावित ज़िलों को 5-5 लाख रुपए तक फंड: मुख्य सचिव ने जेनरिक के साथ ब्रॉन्डेड दवा को दी मंजूरी 4
- श्रीनाथपुरम् स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास 4
- पाँच दिवसीय 'हथकरघा उत्सव' का शुभारंभ 5
- माइनिंग, ऑयल और गैस कॉन्क्लेव 5
- स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में चयनित 26 विद्यालय सम्मानित 6
- मतदाता पहचान-पत्र से आधार नंबर जोड़ने में राजस्थान पूरे देश में द्वितीय 7
- जयपुर में राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह का शुभारंभ 7
- वोटर आईडी से आधार संख्या जोड़ने में पूरे देश में राजस्थान प्रथम 8
- राज्यपाल ने 'शौर्य कला प्रदर्शनी' का उद्घाटन किया 8
- उतर भारत का प्रसिद्ध गोगाजी मेला ध्वजारोहण के साथ हुआ शुरू 9
- 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड 9
- राजस्थान के नागरिक सुरक्षा विभाग के दो अधिकारियों को महामहिम राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक दिये जाने की घोषणा 9
- सामाजिक समरसता अभियान 10
- राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के सफल आयोजन हेतु ग्राम पंचायत व खंड स्तर पर होगा समितियों का गठन 10
- मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 11
- राजस्थान डिजिफेस्ट-2022 11
- मुख्यमंत्री ने किया 'राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी' का उद्घाटन 12
- मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी युवा मित्र संवाद एप तथा कोटा, बीकानेर एवं चूरू में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया 13
- प्रदेश की पहली मोटर मार्केट का लोकार्पण 13
- राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के शुभंकर का अनावरण 14
- महिला समानता दिवस के अवसर पर पाँचदिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन 15
- जोधपुर में गठित होगी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थाई पीठ 15
- ब्यावर सहित छ: ज़िला मुख्यालयों में विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित 16
- 'इन्वेस्टर्स मीट एंड एमओयू साइनिंग सेरेमनी': राज्य सरकार और निवेशकों के बीच 69,789 करोड़ रूपए के एमओयू 16
- राजस्थान के दो शिक्षक-शिक्षिका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित 17
- स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिये राजस्थान को मिला अवार्ड 18
- डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी में राजस्थान अव्वल 18
- मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान 'महिला निधि' का लोकार्पण 19
- केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर में 4 नई सुविधाओं का उद्घाटन 19
- राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 का राज्यस्तरीय शुभारंभ 20
- इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना 20

नोट :

राजस्थान

आयरन ओर ब्लॉक नीलामी में राजस्थान ने रचा नया इतिहास

चर्चा में क्यों ?

31 जुलाई, 2022 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (माइंस एवं पेट्रोलियम) डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जयपुर के बागावास ब्लॉक की आयरन ओर माइनिंग ब्लॉक की ई-नीलामी रिज़र्व प्राईस से 452 प्रतिशत अधिक राशि पर हुई है, जो पूरे देश के माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि खनिज नीलामी नियम 2015 के प्रभाव में आने के बाद समूचे देश में अब तक की यह सबसे अधिक प्रीमियम राशि पर नीलामी है। इससे पहले मध्य प्रदेश में खनिज रॉक फॉस्फेट के ब्लॉक की नीलामी में सर्वाधिक 320 प्रतिशत बोली प्राप्त हुई थी।
- डॉ. अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा जयपुर ज़िले के विराटनगर के पास बागावास में 5.9266 हेक्टेयर आयरन ओर ब्लॉक के आवंटन के लिये अंतिम नीलामी प्रक्रिया में उच्चतम बोली भटिंडा के शुभ लोहिया प्रो. भारत कोल ट्रेडर्स भटिंडा, पंजाब ने 452 प्रतिशत लगाई।
- उन्होंने बताया कि बागावास की आयरन ओर की इस माइनिंग ब्लॉक की नीलामी से राज्य सरकार को आगामी 50 सालों में रॉयल्टी, प्रीमियम, डीएमएफटी, एनएमईटी आदि को मिलाकर 119.65 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान में आयरन ओर के विपुल भंडार होने के साथ ही विभाग द्वारा नई खोज व नीलामी के लिये ब्लॉक तैयार करने का कार्य जारी है।
- जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, करौली, भीलवाड़ा और अलवर में खनिज आयरन ओर के विपुल भंडार उपलब्ध हैं। प्रदेश में वर्तमान में जयपुर में 4, सीकर में 3, झुंझुनूं में 6, भीलवाड़ा में 2 और अलवर में 1 सहित आयरन ओर के कुल 16 खनन पट्टे कार्यशील हैं और एक अनुमान के अनुसार इनसे 50 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना राजस्व प्राप्त हो रहा है।

भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

30 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- समारोह में भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव (कृषि) दिनेश कुमार तथा रजिस्ट्रार (सहकारिता) मुक्तानंद अग्रवाल को पुरस्कार दिया।
- राजस्थान को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला है।
- रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि एग्री इंफ्रा फंड योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट्स (राशि 747.17 करोड़ रुपए) की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में कुल 781 प्रोजेक्ट्स अनुमोदित किये गए हैं। प्रोजेक्ट्स हेतु वितरण की गई ऋण राशि (559.50 करोड़ रुपए) की दृष्टि से भी राज्य का देश में दूसरा स्थान है। अब तक राज्य में कुल 713 प्रोजेक्ट्स को ऋण दिया गया है।

नोट :

- कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, कृषकों, कृषक उत्पाद संगठनों, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, कृषि उद्यमियों इत्यादि को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स तथा कम्यूनिटी फार्मिंग असेट्स बनाने के लिये ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हुए इस पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। ब्याज अनुदान लाभ हेतु योजना की अवधि वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक है।
- रजिस्ट्रार ने बताया कि योजना से वेयर हाउस, साईलो, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सुविधा, पैक हाउस, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ग्रेडिंग एवं सोर्टिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, फल पकाने के कक्ष इत्यादि इकाइयों को लाभ मिल सकेगा।
- सामुदायिक कृषि परियोजनाओं में ऑर्गेनिक इनपुट के उत्पादन की इकाइयों, स्मार्ट एवं प्रिसीजन फार्मिंग के लिये ढाँचागत विकास, क्लस्टर्स में सप्लाई चैन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इन क्षेत्रों में पीपीपी आधारित प्रोजेक्ट्स आदि को लाभ मिल सकेगा।
- राजस्थान सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के साथ उक्त ए.आई.एफ. योजना का समावेशन किया गया है, जिसमें पूंजीगत अनुदान अधिकतम 50 प्रतिशत एवं ब्याज अनुदान अधिकतम 6 प्रतिशत दिया जा रहा है।
- नाबार्ड की पैक्स व लैम्प्स को बहुसेवा केंद्रों में परिवर्तित करने की योजना के साथ समावेशन कर उक्त योजनाओं का लाभ भी सहकारी समितियों को दिया जा रहा है। राज्य में सहकारिता विभाग को योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग बनाया गया है।

राजस्थान में 'लंपी' वायरस प्रभावित ज़िलों को 5-5 लाख रुपए तक फंड: मुख्य सचिव ने जेनरिक के साथ ब्रॉन्डेड दवा को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2022 को मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने 'लंपी' वायरस की स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी बैठक बुलाई। 'लंपी' वायरस ने राजस्थान के 11 ज़िलों को चपेट में ले लिया है। 3 हज़ार से ज्यादा गोवंश इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने सचिवालय से सभी प्रभावित ज़िलों के कलेक्टर्स और पशुपालन विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को कहा कि बीमारी से निपटने के लिये जेनेरिक के साथ ब्रॉन्डेड दवा भी खरीदी जा सकती हैं।
- प्रभावित ज़िलों के लिये 5-5 लाख रुपए का फंड देने पर सहमति बनी है। आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग ज़िलों में 2 से 12 लाख रुपए जारी किये जाएंगे।
- एडिशनल डायरेक्टर (हेल्थ) डॉ. एन.एम. सिंह ने बताया कि केंद्र से आई टीम ने जोधपुर, नागौर का दौरा किया था। अब टीम गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, राजसमंद भी जाएगी।
- डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और गुजरात बॉर्डर से सटे ज़िलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर बकरियों को होने वाली 'माता' से बचाव वाली 'गोट पॉक्स' वैक्सीन गोवंश को लगाने की सलाह दी है।

श्रीनाथपुरम् स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

31 जुलाई, 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने श्रीनाथपुरम् स्टेडियम में सिंथेटिक एथेलेटिक्स ट्रैक का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- श्रीनाथपुरम् स्टेडियम में बन रहा 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक 8 लेन का होगा। फुल पीयूआर सिस्टम से बन रहे इस सिंथेटिक ट्रैक को बनाने में करीब 7 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके निर्माण कार्य के लिये 12 माह का समय निर्धारित किया गया है।

नोट :

- खेलो इंडिया के तहत 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक बनने से कोटा के युवा खिलाड़ियों को हर मौसम में बिना व्यवधान के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुसार तैयारी का अवसर मिलेगा।
- स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने इस अवसर पर कहा कि कोटा में जे.के. पैवेलियन स्टेडियम में 30 करोड़ रुपए की लागत से खेल संकुल बनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न खेलों के लिये इंडोर स्टेडियम की सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। मल्टीपर्पज स्कूल में भी हॉकी सहित कई खेल ग्राउंड विकसित किये जा रहे हैं।

पाँच दिवसीय 'हथकरघा उत्सव' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2022 को राजस्थान के उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने 'हथकरघा उत्सव' का शुभारंभ किया। यह उत्सव 7 अगस्त तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर वीनू गुप्ता ने पश्चिम बंगाल, बाड़मेर, कोटा और बनारस के बुनकरों के साथ बातचीत की तथा जामदानी साड़ी, पट्टू, कोटा डोरिया और बनारसी साड़ी का लाइव प्रदर्शन भी देखा।
- उन्होंने कार्यक्रम में परंपरागत हथकरघा बुनकरों को सम्मानित किया। कोटा ज़िले के कैथून से हसीना बानो, अजमेर ज़िले के जूनिया से मीना देवी, कालूराम और मनोहर लाल तथा धनाउ, बाड़मेर से मोडा राम को इस अवसर पर उनकी रचनात्मकता के लिये सम्मानित किया गया।
- गौरतलब है कि 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 2022 के अवसर पर राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर तथा बुनकर सेवा केंद्र के सहयोग से 'हथकरघा उत्सव' मनाया जा रहा है।
- कार्यक्रम के तहत विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के क्रिएटिव डिज़ाइन विभागों की भागीदारी के साथ पाँच दिवस तक वीव-वॉक, वीव-टॉक, हैंडलूम क्विज़, पैनल डिस्कशन जैसी विभिन्न गतिविधियाँ राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम के सी-स्कीम स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित होंगी।
- इस कार्यक्रम में निगम द्वारा आमजन के लिये बिक्री हेतु 25 प्रतिशत की विशेष छूट के साथ राज्य के बुनकरों के उम्दा हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और राष्ट्र के सामाजिक विकास में हथकरघा उद्योग के महत्त्व के बारे में जागरुकता पैदा करने तथा हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा पर्यावरण के अनुकूल है और जीवनयापन करने का एक व्यवहार्य तरीका है।

माइनिंग, ऑयल और गैस कॉन्क्लेव

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2022 को राजस्थान के जयपुर ज़िले के होटल मैरियट में एकदिवसीय माइनिंग, ऑयल एवं गैस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने किया। उन्होंने कहा कि विगत साढ़े तीन साल में प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में तेज़ी से काम हुआ है और खनिज खोज, नए प्रधान एवं अप्रधान खनिजों के प्लॉट विकसित कर नीलामी करने से लेकर राजस्व अर्जन तक उपलब्धियों का कीर्तिमान बनाया गया है।

नोट :

- इस कॉन्क्लेव में 'हाइड्रोकार्बन सिनेरियो- अवसर एवं चुनौतियाँ' सत्र में पैनल डिस्कशन में भारत एवं राजस्थान में हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र और राजस्थान स्थित बाड़मेर रिफाइनरी का प्रदेश के विकास में योगदान एवं पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में तेज़ी से हो रहे विकास पर मंथन किया गया। इस सत्र में देश व प्रदेश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सिनेरियो एवं भावी संभावनाओं पर चर्चा की गई।
- एक अन्य सत्र में ट्रेंड्स एंड आइडियाज इन माइंस एंड मिनरल सेक्टर पर भारत और राजस्थान की खनिज संपदा एवं सामाजिक तथा आर्थिक विकास में योगदान पर चर्चा हुई। इसके साथ ही तकनीक और नवाचारों से इस क्षेत्र में सस्टेनेबल माइनिंग द्वारा बेस्ट आउटकम पर मंथन किया गया।
- कॉन्क्लेव के सीमलेस गैस ड्रिस्ट्रीब्यूशन एंड पाइपलाइन नेटवर्क सत्र में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (सीजीडी) विकसित करने के प्रयासों के साथ ही भूमिगत गैस पाइपलाइन डालने, प्रेशर रेगुलेटिंग स्टेशन और सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श हुआ।
- खान मंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई खनिज नीति अधिक अग्रगामी, माइनिंग सेक्टर को तेज़ी से प्रमोट करने वाली और समाज के सभी वर्गों को माइनिंग से जोड़ने वाली होगी। नई खनिज नीति में एससी, एसटी, महिलाओं, विशेष योग्यजन, बेरोज़गार टेक्नोक्रेट युवाओं आदि के लिये माइनिंग आवंटन प्रक्रिया में आरक्षण होगा।
- राज्य में माइनिंग सेक्टर से आमनागरिकों को जोड़ने के प्रावधान किये जा रहे हैं। प्रधान और अप्रधान खनिज क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये ही पहली बार राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार और तीन करोड़ 80 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया है।
- खनिज खोज कार्य को गति देने के लिये आरएसएमईटी का गठन, बजरी के विकल्प के रूप में एम सैंड नीति लागू कर सरकारी निर्माण कार्य में 25 प्रतिशत एम सैंड के उपयोग, सिलिकोसिस नीति आदि लागू कर कार्यों को गति दी जा रही है।
- राजस्थान में तेल और गैस सेक्टर की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि चार बेसिनों में विभाजित 14 ज़िलों में प्रचुर मात्रा में ऑयल व गैस की 11 लीज़ स्वीकृत हैं। प्रदेश में एक लाख 9 हज़ार बैरल खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है।
- एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान यूनिक प्रदेश बन गया है। यहाँ लेड, जिंक, बोलेस्टाइन, कॉपर, यूरेनियम, पोटाश, लाइमस्टोन, आयरन ओर, मैंगनीज़, गारनेट, जिप्सम, मार्बल, सैंड स्टोन आदि के विपुल भंडार है। यूरेनियम खोज के साथ ही राजस्थान विश्वपटल पर आ गया है, प्रचुर मात्रा में पोटाश के भंडार मिले हैं, आयरन ओर के जयपुर ज़िले के बागावास ब्लॉक की नीलामी देश में सर्वाधिक 452 प्रतिशत प्रीमियम पर हुई है।
- डॉ. अग्रवाल ने बताया कि ऑयल और गैस के कारण पश्चिम राजस्थान में रिव्यूलेशन आ गया है। राज्य में बाड़मेर की पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक हो गई है। राजस्थान रिफाइनरी की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुर्ज खलीफा से 5 गुणा अधिक कंक्रीट और एफिल टॉवर से 40 गुणा अधिक स्टील का उपयोग होगा। आगामी 8 सालों में 96 लाख पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का रोडमैप बनाया गया है।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में चयनित 26 विद्यालय सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

5 अगस्त, 2022 को होटल क्लॉर्क आमेर में आयोजित सम्मान समारोह में भारत सरकार के 'स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22' प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राज्य के 26 विद्यालयों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- सत्र 2021-22 के लिये आयोजित की गई 'स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार' प्रतियोगिता में राज्य के 46,633 राजकीय एवं निजी विद्यालयों ने हिस्सा लिया था।
- प्रतियोगिता दो श्रेणियों में हुई थी, जिसमें पहली श्रेणी संपूर्ण अंक पर आधारित थी, जबकि दूसरी श्रेणी; 06 उप-श्रेणियों (जल, शौचालय, साबुन से हाथ धुलाई, संचालन एवं रख-रखाव, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण तथा कोविड-19 से बचाव) पर आधारित थी।
- संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से करवाई गई। पंजीकृत विद्यालयों का ज़िला कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा मूल्यांकन कर ज़िला स्तर से कुल 406 विद्यालयों को चिह्नित किया गया था।

नोट :

- राज्यस्तरीय गठित दल द्वारा ज़िले के सहयोग से 406 विद्यालयों का अंतिम रूप से मूल्यांकन करते हुए कुल 26 श्रेष्ठ विद्यालयों का चयन किया गया, जिनमें से 20 विद्यालय संपूर्ण अंक आधारित श्रेणी में एवं 6 विद्यालयों का उप-श्रेणी में से चयन किया गया।
- चयनित किये गए 26 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के चयनित विद्यालयों के साथ स्वच्छता के मानकों पर आधारित इस प्रतियोगिता में राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित विद्यालयों को सम्मान स्वरूप 25 हज़ार रुपए की राशि प्रति विद्यालय दी गई।

मतदाता पहचान-पत्र से आधार नंबर जोड़ने में राजस्थान पूरे देश में द्वितीय

चर्चा में क्यों ?

5 अगस्त, 2022 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में मतदाता पहचान-पत्र से आधार संख्या जोड़ने के लिये चलाए जा रहे अभियान में 12 लाख से अधिक मतदाता-पहचान पत्रों को आधार संख्या से जोड़कर पूरे देश में राजस्थान द्वितीय स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में मतदाता पहचान-पत्र से आधार संख्या जोड़ने के लिये विशेष अभियान सीईओ से बीएलओ तक चलाया जा रहा है। एक अगस्त से प्रारंभ हुए इस अभियान में अब तक 12 लाख से अधिक मतदाता पहचान-पत्रों को आधार संख्या से जोड़ा जा चुका है।
- प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा अभिनव पहल करते हुए इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा सरकारी, गैर-सरकारी, निजी कार्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से स्वयं ही आधार नंबर से मतदाता पहचान-पत्र जोड़ने की हैंड्स ऑन जानकारी दी जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि एक अगस्त से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत अपनी पहचान स्थापित करने के लिये अब प्रत्येक मतदाता अपने मतदाता पहचान-पत्र के साथ आधार नंबर जोड़ सकता है। इसके लिये एक नवीन फॉर्म 6 बी भरा जा सकता है। आधार नंबर जोड़ने का कार्य नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी), वोटर हेल्पलाइन ऐप, गरुड़ ऐप या क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से भी किया जा सकता है।

जयपुर में राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

7 अगस्त, 2022 को राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त महेंद्र कुमार पारख ने जयपुर के सबसे बड़े और व्यस्त मॉल वर्ल्ड ट्रेड पार्क में राजस्थान के बुनकरों और हस्तशिल्पियों को बाज़ार से जोड़ने की कड़ी में राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि नाबार्ड द्वारा राजस्थान के विभिन्न ज़िलों के बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों के उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री के लिये 7 अगस्त से 11 अगस्त तक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सप्ताह मनाया जा रहा है।
- राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन ज़िलों से आए बुनकरों, हस्तशिल्पियों द्वारा लाए गए उत्पादों के 10 स्टॉल लगाए गए हैं।
- इन स्टालों में विभिन्न उत्पाद बाड़मेर से कशीदाकारी उत्पाद, जोधपुर के सलावास की दरी, उदयपुर के पॉटरी उत्पाद, कोटा से कोटा डोरिया साड़ी, सूट, ड्रेस मटीरियल आदि, अजमेर से किशनगढ़ कला शैली के चित्र और गुलकंद उत्पाद, सीकर और अलवर से चमड़े की राजस्थानी जूती उत्पाद, अलवर की लकड़ी की पेंटिंग और जयपुर के बगरु से बगरु प्रिंट इत्यादि की बिक्री की जा रही है।

नोट :

वोटर आईडी से आधार संख्या जोड़ने में पूरे देश में राजस्थान प्रथम

चर्चा में क्यों ?

10 अगस्त, 2022 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़ने के अभियान में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 55 लाख से अधिक मतदाताओं द्वारा मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार कार्ड से जोड़ा गया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि एक अगस्त से प्रारंभ हुए इस अभियान में पूरे देश में अब तक 2 करोड़ 52 लाख मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड से लिंक किये गए। जिसमें से राज्य में 55 लाख 86 हज़ार 710 मतदाताओं ने अपने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ लिया है।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में इसके लिये 'सीईओ से बीएलओ'तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
- निर्वाचन विभाग द्वारा अभिनव पहल करते हुए इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा सरकारी, गैर-सरकारी, निजी कार्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से स्वयं ही आधार नंबर से मतदाता पहचान-पत्र जोड़ने की हैंड्स ऑन जानकारी दी जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि एक अगस्त से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत अपनी पहचान स्थापित करने के लिये अब प्रत्येक मतदाता अपने मतदाता पहचान-पत्र के साथ आधार नंबर जोड़ सकता है। इसके लिये एक नवीन फॉर्म 6-बी भरा जा सकता है। आधार नंबर जोड़ने का कार्य नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी), वोटर हेल्पलाइन ऐप, गरुड़ ऐप या क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से भी किया जा सकता है।

राज्यपाल ने 'शौर्य कला प्रदर्शनी' का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

9 अगस्त, 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जवाहर कला केंद्र में 'शौर्य कला प्रदर्शनी'का उद्घाटन किया। यह कला प्रदर्शनी 20 अगस्त, 2022 तक चलेगी।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रदर्शनी का आयोजन पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के तीन दिवसीय 'रंग स्वाधीन' समारोह के अंतर्गत किया गया है।
- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र, उनके जीवन तथा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाओं को आकर्षक कलाकृतियों के रूप में संजोया गया है।
- उल्लेखनीय है कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा कोविड काल में शौर्य कला शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें देश भर के कलाकारों द्वारा स्वाधीनता संग्राम एवं स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित कलाकृतियों का निर्माण किया गया था।
- राज्यपाल ने इस अवसर पर केंद्र द्वारा तैयार करवाए गए मांडणा कलाकृतियों के एलबम और 'पंचतंत्र कथा मंजरी'का लोकार्पण भी किया।
- इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों की शौर्य गाथा को चित्रों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। देश की आजादी के लिये अमूल्य योगदान देने वाली महान विभूतियों के बारे में जानने की प्रेरणा युवा पीढ़ी को इन चित्रों से मिलेगी।

नोट :

उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगाजी मेला ध्वजारोहण के साथ हुआ शुरू

चर्चा में क्यों ?

11 अगस्त, 2022 को देवस्थान, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले का पूजा-अर्चना के बाद ध्वजारोहण कर विधिवत् रूप से शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मेला शुभारंभ के मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री शकुंतला रावत ने गोगाजी मंदिर के सामने लगी अस्थाई वैरीकेटिंग को स्थाई करने, मंदिर के सामने मुख्य गेट तक इंटरलॉक सड़क बनाने व पक्के शेड बनाने की घोषणा की।
- गौरतलब है कि राजस्थान के पाँच पीरों में से एक लोकपूज्य देवता गोगाजी की याद में प्रतिवर्ष गोगामेड़ी (हनुमानगढ़) में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक विशाल मेला लगता है।
- वीर गोगाजी नागवंशीय चौहानों के वंशज राजा जेवर सिंह के पुत्र थे। मान्यता है कि इनका जन्म गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। इन्हें राजस्थान में सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है।
- इनका जन्म राजस्थान में चूरू ज़िले के राजगढ़ तहसील के ददरेवा में विक्रम संवत् सन् 1003 में हुआ था। इन्हें महमूद गज़नवी का समकालीन माना जाता है।
- जाहरवीर गोगाजी उत्तर भारत में लोकप्रिय देवता हैं। गोगाजी को राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी लोकदेवता के रूप में पूजा जाता है।

1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

12 अगस्त, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में सवाई मान सिंह स्टेडियम में प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।

प्रमुख बिंदु

- आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत राज्य, ज़िला, ब्लॉक व विद्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग व कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन किया।
- बच्चों ने झंडा ऊँचा रहे हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, आओ बच्चों तुम्हे दिखाएँ झाँकी हिंदुस्तान की, हम होंगे कामयाब जैसे देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों के साथ राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्'व राष्ट्रगान 'जन गण मन'का भी गायन किया।
- इस अवसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के उपाध्यक्ष प्रथम भल्ला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विश्व रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया, जिसे मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों व समस्त प्रदेशवासियों को समर्पित किया।

राजस्थान के नागरिक सुरक्षा विभाग के दो अधिकारियों को महामहिम राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक दिये जाने की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

14 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नागरिक सुरक्षा विभाग के दो अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक दिये जाने की घोषणा की गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जिन दो अधिकारियों को महामहिम राष्ट्रपति के नागरिक सुरक्षा पदक दिये जाने की घोषणा की गई है, उनमें अलवर ज़िले के कलेक्टर और नियंत्रक नागरिक सुरक्षा जितेंद्र कुमार सोनी तथा जगदीश प्रसाद रावत, उप-नियंत्रक (सेवानिवृत्त) शामिल हैं।
- जितेंद्र कुमार सोनी ने झालावाड़, जालोर व नागौर ज़िले के कलेक्टर रहते विभिन्न आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों में उत्कृष्ट कार्य किये हैं। इन्हें जालोर कलेक्टर रहते अपनी जाने की परवाह किये बिना, बाढ़ में फँसे 8 लोगों को जीवित निकालने पर पूर्व में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति महोदय का 'जीवन रक्षक पदक'से नवाजा जा चुका है।
- इसके साथ ही इन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर में वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक नागरिक सुरक्षा का अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2022 के अवसर पर इन्हें 'राष्ट्रपति महोदय के नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक'दिये जाने की घोषणा की गई है।
- इसी प्रकार जगदीश प्रसाद रावत को नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन में सराहनीय व उत्कृष्ट सेवाओं के लिये 15 अगस्त 2022 के अवसर पर 'राष्ट्रपति महोदय के नागरिक सुरक्षा विशिष्ट सेवा पदक'दिये जाने की घोषणा की गई है।

सामाजिक समरसता अभियान

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने शासन सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश भर में 'सामाजिक समरसता अभियान' चलाने और अभियान की कार्य योजना बनाने के लिये निर्देशित किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि हाल ही में जालौर में स्कूल टीचर द्वारा बच्चे की पिटाई के बाद हुई मौत की घटना के संबंध में शासन सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
- उन्होंने बताया कि अभियान के तहत संविधान एवं अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में आम जन में जागरूकता लाई जाएगी। लोगों को समरसता, जोकि सभी धर्मों, विचारों और समाज को एकता के सूत्र में पिरोती है, के संबंध में जागरूक किया जाएगा।
- इसके साथ ही मंत्री टीकाराम जूली ने गृह, उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिये। उन्होंने बच्चों के साथ खाने-पीने, बैठने, कार्य करने व अन्य किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने के लिये उच्च शिक्षा व स्कूल शिक्षा विभाग को तथा अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में प्राथमिकता से जाँच करते हुए शीघ्र चालान पेश करने के संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिये।
- उन्होंने अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित ज़िला व ब्लॉकस्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के बैठकें समय-समय पर आयोजित करने के भी निर्देश दिये।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के सफल आयोजन हेतु ग्राम पंचायत व खंड स्तर पर होगा समितियों का गठन

चर्चा में क्यों ?

18 अगस्त, 2022 को राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव नवीन जैन ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स-2022 के आयोजन की तैयारियों को लेकर सभी ज़िलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत व खंड स्तर पर समितियों के गठन के निर्देश जारी किये।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स-2022 के लिये ग्राम पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताएँ 29 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य आयोजित होंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर विजेता टीम खंड स्तर पर 12 सितंबर से आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी।
- ग्राम पंचायत स्तर पर समिति- समिति के संयोजक ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे। राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य, ग्राम सचिव, पटवारी तथा शारीरिक शिक्षक समिति के सदस्य होंगे।
- खंड स्तर पर समिति- खंड स्तर समिति के संयोजक पंचायत समिति के उपखंड अधिकारी होंगे तथा ब्लॉक विकास अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसमें ब्लॉक पंचायत समिति के प्रधान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व ज़िला खेल अधिकारी का प्रतिनिधि तथा राजकीय शारीरिक शिक्षक सदस्य होंगे।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। 29 अगस्त से शुरू होने वाले इस आयोजन में गाँव-ढाणी की खेल प्रतिभाओं को राज्यस्तरीय मंच मिलेगा और प्रदेश को भविष्य के लिये उभरते खिलाड़ी मिलेंगे।
- इन खेलों के लिये 30 लाख ग्रामीणों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें कबड्डी, खो-खो, टेनिसबॉल क्रिकेट, वालीबॉल, हॉकी और शूटिंग जैसे खेल खेले जाएंगे। ज़िलों के बाद विजेता टीमों के बीच राज्यस्तरीय खेल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होंगे।

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश की तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने राज्य की 'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना' में रुचि दिखाई है। इस योजना के तहत राज्य में 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाना है।

प्रमुख बिंदु

- परियोजना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि 'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना'के लिये तकनीकी बोली पेश करने वाली चार में से तीन कंपनियां इसमें शामिल हुईं। अब एक उच्च स्तरीय समिति निविदाओं का आकलन कर आगे फैसला करेगी।
- इस प्रक्रिया का जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है ताकि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बजटीय घोषणा को अमली जामा पहनाया जा सके।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में 'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना'की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य में 1.35 करोड़ 'चिरंजीवी परिवारों'की महिला मुखिया को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना है। फोन में तीन साल तक इंटरनेट के अलावा वाइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी।
- मोबाइल फोन, तीन साल के इंटरनेट सहित अन्य मदों को मिलाकर यह परियोजना लगभग 12000 करोड़ रुपए की है। दिये जाने वाले मोबाइल में दो सिम लग सकेंगे और इसके 'प्राइमरी स्लॉट'में सिम पहले से ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसे बदला नहीं जा सकेगा।
- इस मोबाइल का उपयोग राज्य सरकार 'चिरंजीवी परिवारों'को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये करेगी। इसके साथ ही, वह इसके जरिये अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर सकेगी और उसके पास योजनाओं का लाभ लेने वालों का डाटा भी रहेगा।

राजस्थान डिजिफेस्ट-2022

चर्चा में क्यों ?

19-20 अगस्त, 2022 को तकनीक एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान डिजिफेस्ट-2022 का आयोजन किया गया। इस दोदिवसीय डिजिफेस्ट-2022 में युवाओं ने अपने स्टार्टअप के साथ बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस बहुआयामी आयोजन में युवा स्टार्टअप्स, निवेशक, कॉरपोरेट्स, और शिक्षाविद् एक मंच पर आए।
- दोदिवसीय डिजिफेस्ट में राज्य भर से विभिन्न विश्वविद्यालयों और एटीएल का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यताप्राप्त 45 आईस्टार्ट स्टार्टअप ने अपने स्टार्टअप उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया। इस सभी स्टार्टअप को उत्पादों एवं सेवाओं की सीधी खरीद के लिये सरकारी अधिकारियों के सामने उनकी बातचीत की सुविधा मिली।
- स्टार्टअप बाज़ार में उत्पाद आधारित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 30 स्टार्टअप को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री का अवसर दिया जा रहा है।
- डिजिफेस्ट में विभिन्न उद्योग, निकायों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थकों को चर्चा आयोजित कर भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया, जिसमें स्टार्टअप और युवा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारक शामिल हुए।
- इन सम्मेलनों में देश भर से आमंत्रित वक्ताओं ने न केवल सरकार को प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दी, बल्कि स्टार्टअप्स और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य प्रमुख हितधारकों के लिये संबंध भी बनाए।
- डिजिफेस्ट में राजस्थान के 50 से अधिक विद्यालयों के 3000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने बी-क्विज, एड-एमएडी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य राजस्थान के युवा छात्र-छात्राओं को पारिस्थितिकी तंत्र से अवगत कराना था।
- इस अवसर पर संभाग एवं ज़िलास्तरीय 51 छात्र-छात्राओं को स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूल इनोवेशन चैलेंज और 23 विद्यार्थियों को रूरल आईस्टार्ट प्रोग्राम के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया।
- गौरतलब है कि राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, 2015 के तहत मूल्यांकन समिति और राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा 67 स्टार्टअप्स को लगभग 441 करोड़ रुपए के फंडिंग मूल्य के साथ फंडिंग का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने किया 'राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी' का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

20 अगस्त, 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में 'राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी'(आर-कैट) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत व उभरती प्रौद्योगिकी सीखने का अवसर मिलेगा।
- इन क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों के विशेषज्ञों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वस्तरीय आई.टी. फिनिशिंग स्कूल में युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिलेगी। तकनीक स्नातकों को आईटी प्रौद्योगिकी में 6 महीने तक का प्रशिक्षण मिलेगा। इससे युवाओं को रोज़गार के उत्कृष्ट अवसर मिलेंगे और वे राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में आईटी सेक्टर को मज़बूत करने के लिये जोधपुर में 650 करोड़ रुपए की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा संभागीय मुख्यालयों पर भी जल्द ही राजीव गांधी के नाम से आईटी शिक्षा के संस्थान स्थापित किये जाएंगे।
- राज्य में सरकार एवं उद्योग जगत् की मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्ण तकनीकी जनशक्ति उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विश्वस्तरीय सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को अपनाते हुए आईटी क्षेत्र की अग्रणी संस्थाओं के साथ सहभागिता के आधार पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये आर-कैट को 2022 में राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार के संरक्षण में स्थापित किया गया है।

नोट :

- अब इस संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई-एमएल) ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी (एआर/पीआर) बिग डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और टम कंप्यूटिंग आदि पर भागीदार संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों को विश्वस्तरीय सर्टिफिकेट भी दिये जाएंगे।
- आर-कैट युवाओं और कामकाजी पेशेवरों के विकास, तकनीकी और सॉफ्ट स्किल्स के लिये फिनिशिंग स्कूल के रूप में कार्य करेगा, ताकि उन्हें उद्योग आधारित मांग के अनुरूप तैयार किया जा सके एवं उद्योग अपडेट सहकार्य पहले से स्थापित प्रयोगशालाओं के उपयोग आदि के लिये स्टार्ट-अप का समर्थन किया जा सके।
- यहाँ ओरेकल वीएमवेयर एसएएस रेडहैट सिस्कों एवं कैडओटाफिना जैसे वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के सहयोग से बीई, बीटेक, बीसीए, एमसीए एमबीए और एमएससी (आईटी) जैसे पेशेवर स्नातकों के लिये एक सप्ताह से छह महीने तक की अवधि के उन्नत और उभरती आईटी आधारित प्रमुख तकनीकी, जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई-एमएल) ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी (एजार / वीआर), बिग डाटा एनालिटिक्स रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगें।

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी युवा मित्र संवाद एप तथा कोटा, बीकानेर एवं चूरू में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया

चर्चा में क्यों ?

20 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिड़ला सभागार में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट के समापन समारोह में कोटा, बीकानेर और चुरू में वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- स्टार्टअप्स को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिये जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के बाद इन तीन ज़िलों में सेंटर स्थापित किये गए हैं। इन सेंटर में आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले तीन सालों के ई-गवर्नेंस पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। साथ ही स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम व रूरल आईस्टार्ट प्रोग्राम के अंतर्गत 74 विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी वितरित की।
- उन्होंने आमजन के लिये उपयोगी साबित होने वाली तीन वेबसाइट्स 'वेबमायवे', 'सोट्टो' एवं 'राजसंबल'और राजीव गांधी युवा मित्र संवाद एप का भी लोकार्पण किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ही राजस्थान पूरे देश में कोरोना प्रबंधन में अग्रणी रहा। इस दौरान लगभग 500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर तक के सदस्य जुड़े।
- दवाइयाँ एवं चिकित्सा उपकरणों के प्रबंधन, लॉकडाउन के दौरान रोज़गार खोने वाले मज़दूर वर्ग, ठेले-रेहडी वालों के सर्वे में भी आईटी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इस दौरान लगभग 35 लाख लोगों के खातों में आर्थिक सहयोग राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई।
- मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के अंतर्गत 200 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सरकारी खर्चे पर देश-विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिये भेजा जा रहा है।

प्रदेश की पहली मोटर मार्केट का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

21 अगस्त, 2022 को राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश की पहली सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का कोटा में लोकार्पण कर मोटर व्यवसायियों को बड़ी सौगात प्रदान की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस मोटर मार्केट से शहर में विभिन्न स्थानों में मोटर व्यवसाय करने वाले नागरिकों को सुविधाएँ मिलने के साथ शहर में जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी।
- स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि यह प्रदेश की पहली सुव्यवस्थित मोटर मार्केट है, जिसमें मोटर व्यवसाय करने वाले नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएँ मिलेंगी। यहाँ एक ही स्थान पर पुराने वाहन खरीदने वालों को भी अनेक विकल्प मिलेंगे।
- उन्होंने कहा कि नगर विकास द्वारा यहाँ सभी सुविधाओं का निर्माण कराया गया है, मोटर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों से केवल दुकान निर्माण की लागत लेकर दुकान का मालिकाना हक प्रदान किया गया है।
- स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि शहर में पशुपालकों की सुविधा के लिये देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना बनाई गई है, जिसमें पशुपालकों के लिये सभी सुविधाओं का समावेश किया गया है। इससे पशुपालकों को दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियों से निजात मिली है, वहीं शहर में जगह-जगह अनाधिकृत पशुबाड़ों से भी निजात मिली है।
- नगर विकास न्यास द्वारा तैयार की गई प्रदेश की पहली मोटर मार्केट को डीसीएम रोड पर शिवाजी पार्क के पास विकसित किया गया है। इसमें वर्तमान में 247 दुकान निर्मित हैं तथा 9 दुकानों का निर्माण और कराया जाएगा। इसमें व्यवसायियों के लिये चारों ओर सीसी रोड का निर्माण, आधुनिक शौचालय, रोड लाईट, सभी दुकानों का विद्युतीकरण कराया गया है। लगभग 15 बीघा क्षेत्र इसके लिये आरक्षित है।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के शुभंकर का अनावरण

चर्चा में क्यों ?

22 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के इनडोर हॉल में गाँव-ढाणियों में होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के शुभंकर 'शेरू'का अनावरण किया एवं थीम सॉन्ग भी जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 29 अगस्त से शुरू हो रहे ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिये 40 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
- ग्रामीण खिलाड़ियों को खोज कर आगे लाना, उनकी प्रतिभा को तराशना, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा आमजन में खेल भावना को बढ़ावा देना राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक सभी आयुवर्ग के लिये है। इन खेलों में लगभग 30 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं तथा 2 लाख टीमें बनाई गई हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड सहित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है। स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 50 लाख से 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 30 लाख से 1 करोड़ रुपए राशि दी जा रही है।
- इसके अलावा एशियाई एवं राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली 30 लाख, 20 लाख एवं 10 लाख रुपए की ईनामी राशि को बढ़ाकर क्रमश: 1 करोड़, 60 लाख एवं 30 लाख रुपए किया गया है।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरी दी गई है। इसके अलावा प्रशिक्षकों के लिये भी पेंशन स्कीम लागू की गई है। खिलाड़ियों के लिये सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है तथा उन्हें डीएसपी स्तर तक की नौकरियाँ दी जा रही हैं।
- उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर, ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर, ज़िला स्तर पर 22 सितंबर से 25 सितंबर तथा राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक प्रस्तावित है।

नोट :

- खेलों का आयोजन खेल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से किया जा रहा है।
- राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी (बालक/बालिका वर्ग), शूटिंग बॉल (बालक वर्ग), खो-खो (बालिका वर्ग), वॉलीबॉल (बालक/बालिका वर्ग), टेनिसबॉल क्रिकेट (बालक/बालिका वर्ग) एवं हॉकी (बालक/बालिका वर्ग) सहित 6 खेल शामिल होंगे।

महिला समानता दिवस के अवसर पर पाँचदिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

23 अगस्त, 2022 को मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पाँचदिवसीय प्रदर्शनी का जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 27 अगस्त तक खुली रहेगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 'महिला समानता दिवस' के अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पाँचदिवसीय समारोहों की श्रृंखला की शुरुआत की गई है।
- प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न ज़िलों से एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड से आये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न हस्तशिल्प और हस्तकरघा उत्पादों के करीब डेढ़ सौ स्टॉल लगाए गए हैं।
- मुख्य सचिव ने इस अवसर पर अधिकारियों को महिला समूहों की महिलाओं के नियमित प्रशिक्षण, उनके उत्पादों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री में उनकी सहायता और इन समूहों को आंगनबाड़ी से जोड़ने जैसे कई निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह के कई उत्पादों को कॉर्पोरेट गिफ्ट के रूप में बढ़ावा देने की संभावनाएँ देखने के भी निर्देश दिये।
- विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा एवं राजीविका की राज्य मिशन निदेशक एवं ग्रामीण विकास सचिव मंजू राजपाल ने मुख्य सचिव को बताया कि जल्द ही राजीविका द्वारा अमेजॉन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिये एमओयू किया जाएगा।

जोधपुर में गठित होगी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थाई पीठ

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थाई पीठ स्थापित करने की मंज़ूरी दी। साथ ही जोधपुर में स्थाई पीठ का गठन होने तक जोधपुर चल पीठ की बैठक प्रत्येक माह के 8 प्रभावी दिवसों में आयोजित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में न्यायाधीन डी.बी. सिविल रिट पीटिशन में माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 7.2022 की अनुपालना में यह निर्णय लिया गया है।
- इससे राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम, 1976 तथा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण नियम, 1976 में विहित प्रावधानों के क्रम में जोधपुर में अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना के लिये प्रक्रिया शुरू होगी।
- स्थाई पीठ का गठन होने तक जोधपुर में सर्किट बैंच की बैठक अवधि प्रत्येक माह में 8 प्रभावी दिवस होगी।

नोट :

ब्यावर सहित छः ज़िला मुख्यालयों में विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2022 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर ब्यावर (अजमेर ज़िला) सहित छः ज़िला मुख्यालयों पर स्थापित समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव प्रवीर भटनागर ने बताया कि प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिये अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित किया गया है।
- इनमें ब्यावर (अजमेर ज़िला) अलवर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद एवं सीकर मुख्यालयों पर स्थापित समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित किया गया है।
- इन न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित ज़िला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

'इन्वेस्टर्स मीट एंड एमओयू साइनिंग सेरेमनी': राज्य सरकार और निवेशकों के बीच 69,789 करोड़ रूपए के एमओयू

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2022 को 'इन्वेस्ट राजस्थान 2022' के तहत नई दिल्ली में आयोजित 'इन्वेस्टर्स मीट एंड एमओयू साइनिंग सेरेमनी'में राजस्थान सरकार और निवेशकों के बीच 69,789.93 करोड़ रुपए के एमओयू हुए। इससे राज्य में कुल 11846 प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि जयपुर में आगामी 7 और 8 अक्तूबर को होने वाले 'इन्वेस्ट राजस्थान 2022' के तहत नई दिल्ली में 'इन्वेस्टर्स मीट एंड एमओयू साइनिंग सेरेमनी'आयोजित की गई। इस एमओयू सहित अब तक लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू एवं एलओआई हो चुके हैं।
- 69,789.93 करोड़ रुपए के एमओयू में अवड्डा पावर द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए, ओ2 पावर एसजी पीटीई द्वारा अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा सेक्टर में 25,000 करोड़ रुपए, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड द्वारा 1400 करोड़ रुपए, सेंट गोबेन द्वारा 1000 करोड़ रुपए के निवेश से फ्लोट ग्लास मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के प्रस्ताव हैं।
- इसके अलावा वरुण बेवरेजेज लिमिटेड द्वारा 636 करोड़ रुपए की कार्बोनेटेड सॉफ्ट-ड्रिंक्स, फ्रूट-जूस एवं पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। विप्रो जयपुर में हाइड्रोलिक सिलेंडर प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना को लेकर अपार संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिये कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इससे निवेशकों को राज्य में निवेश करने में आसानी हुई है।
- वर्तमान में रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, सौर ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा विकास आदि मंक भारी निवेश करने वाले राज्य के रूप में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान निवेशकों के लिये उपलब्ध अनुकूल नीतिगत ढाँचे से पहली पसंद बना है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि रीको द्वारा राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जा रहे हैं। एनसीआर का 25 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में होने से देशभर से बेहतर कनेक्टिविटी है। राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। इससे निवेशकों को बड़ा फायदा मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि रिप्स के तहत निवेशकों को उनकी जरूरत के अनुसार पैकेज दिये जा रहे हैं। एमएसएमई-2019 के तहत नवीन उद्यम इकाइयों को 3 साल तक किसी सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होने के साथ वन स्टॉप शॉप प्रणाली से सभी सरकारी स्वीकृतियाँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

नोट :

- राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एमएसएमई एवं रिप्स सहित प्रत्येक सेक्टर के लिये पॉलिसी बनाई गई है। जोधपुर ज़िले में 14 हज़ार एकड़ में फैला विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है।
- इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि डीएफसी कॉरिडोर एरिया का 40 प्रतिशत और डीएमआईसी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा राज्य से गुजरता है। सबसे बड़े राज्य और स्ट्रेटेजिक स्थिति के चलते राजस्थान निवेश की विशाल संभावनाएँ प्रदान करता है। निवेश को बढ़ावा देने के लिये हाल ही में वन स्टॉप शॉप, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।
- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि निवेश के लिये राजस्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान बन गया है। राजस्थान को अवसरों की भूमि कहा जाता है। राजस्थान में एक ही पोर्टल पर निवेशकों को विभिन्न अनुमोदन प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार जयपुर में नए कार्गो कॉम्प्लेक्स, एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिये नवीन फैसिलिटी और उदयपुर में नए कार्गो कॉम्प्लेक्स, बीकानेर में आईसीडी के साथ राजस्थान के विकास की दिशा में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है।

राजस्थान के दो शिक्षक-शिक्षिका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

25 अगस्त, 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिये चयनित देश के विभिन्न राज्यों के 46 शिक्षकों के नाम की अंतिम सूची जारी की। इसमें राजस्थान के दो शिक्षक-शिक्षिका के नाम भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु चयनित शिक्षक-शिक्षिकाओं को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर, 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार के तौर पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को 50 हज़ार रुपए की राशि और सिल्वर मेडल दिया जाएगा।
- शिक्षक दिवस पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित राजस्थान के दो शिक्षकों में राजकीय उच्च माध्यमिक बधिर विद्यालय, बीकानेर की विज्ञान शिक्षिका सुनीता और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगियापाड़ा, उदयपुर के शिक्षक दुर्गाराम मुवाल शामिल हैं।
- शिक्षिका सुनीता ने मूक-बधिर बच्चों के साथ विज्ञान शिक्षण के नवाचार के तहत इन विशेष बच्चों को 2017 से लगातार राज्यस्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीयस्तरीय इंस्पायर अवार्ड में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया है। इस विशेष विद्यालय में इन बच्चों ने विज्ञान लैब भी बनाई है। इसके अतिरिक्त विद्यालय की एक छात्रा ने ओलंपियाड में स्थान प्राप्त किया है और रजत पदक प्राप्त कर देश को गौरवान्वित किया है।
- शिक्षक दुर्गाराम शिक्षण के अलावा बाल श्रम एवं बाल तस्करी की रोकथाम को लेकर भी सक्रिय हैं। बालश्रम एवं बाल तस्करी से जुड़े 400 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें वापस शिक्षा से जोड़ा गया है। इनमें 250 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। इसके अलावा शिक्षा में नवाचार, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के बस्ते का भार कम किया गया है।
- शिक्षक दुर्गाराम ने कोरोना टीकाकरण के दौरान योद्धा के रूप में कार्य करके पंचायत मादड़ी को पूरे भारत में सर्वाधिक टीकाकरण वाली पहली जनजाति पंचायत बनाने में मदद की थी। वे उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाली बालिकाओं की पढ़ाई का खर्च स्वयं वहन करते हैं और प्रतिवर्ष एक महीने की सेलरी विद्यालय विकास एवं विद्यालय के बच्चों पर खर्च करते हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के तहत कार्य करते हुए 11000 से ज़्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का काम किया है। साथ ही, निराश्रित बच्चों के अभिभावक बनकर शिक्षा से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं।
- गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- पुरस्कारों के लिये शिक्षकों का चयन ऑनलाइन तीनस्तरीय चयन प्रक्रिया के ज़रिये पारदर्शी तरीके से किया जाता है।

नोट :

- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।

स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिये राजस्थान को मिला अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

25 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव-2022 में राजस्थान को आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये अवार्ड प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल मंत्री डॉ. महेश जोशी ने यह अवार्ड ग्रहण किया।
- डॉ. जोशी ने कहा कि राजस्थान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक गाँवों में आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किये हैं।
- जल जीवन मिशन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जयपुर ज़िले के 15 गाँवों में नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं।
- इस सिस्टम में पेयजल आपूर्ति की लाइन की शुरुआत, पाइप लाइन के ब्रांच नोड एवं टेल नोड पर सेंसर्स लगाए गए हैं। इन सेंसर्स को इंटरनेट से जोड़ा गया है। इंटरनेट के माध्यम से सेंसर्स द्वारा एकत्र डाटा का आदान-प्रदान एवं मॉनिटरिंग की जाती है।
- सेंसर्स के माध्यम से यह भी जानकारी मिलती है कि टंकी का पानी शुद्ध है एवं उसमें किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं है। साथ ही, टेल एंड के उपभोक्ता को जो पानी मिल रहा है, उसका प्रेशर कितना है, फ्लो कैसा है, पीएच वैल्यू, टीडीएस, क्लोरीन एवं फ्लोराइड कितनी मात्रा में है, इसका डाटा भी सेंसर्स से प्राप्त होता है।

डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी में राजस्थान अव्वल

चर्चा में क्यों ?

26 अगस्त, 2022 को राजस्थान के सूचना एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त आशीष गुप्ता ने कहा कि डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में राजस्थान देश में अब सिरमौर राज्य बन गया है। राज्य में कुल एक लाख ई-मित्र संचालित हैं।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में 85 हज़ार ई-मित्र एवं 15 हज़ार ई-मित्र प्लस सहित कुल एक लाख ई-मित्र संचालित हैं, जबकि देश में यह आँकड़ा 3 लाख है। इस प्रकार राजस्थान में पूरे देश के एक-तिहाई ई-मित्र संचालित हैं।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त आशीष गुप्ता ने झालाना डूंगरी स्थित भामाशाह टेक्नो हब में 'आधार उपयोग को सरल बनाने के लिये हालिया पहल' पर एक राज्यस्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
- उन्होंने कहा कि राज्य में पहले सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये या अन्य कार्यों के लिये आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन डिजिटल क्रांति के इस युग में अब सरकार की सारी योजनाएँ मोबाइल फोन पर उपलब्ध हैं तथा डिजिटल सर्विस डिलीवरी से सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ी है।
- सर्विस डिलीवरी में सबसे मुख्य भूमिका डाटा की प्रामाणिकता की होती है। राज्य में यह काम आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। आगामी समय में राज्य में आधार पंजीकरण सौ प्रतिशत करने पर काम किया जा रहा है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान 'महिला निधि' का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

26 अगस्त, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में आयोजित राज्यस्तरीय महिला समानता दिवस समारोह में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये स्थापित प्रथम 'महिला निधि'(राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन) का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस निधि से महिलाओं को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के अलावा व्यवसाय को बढ़ाने व उद्यमिता के लिये सुलभ ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6 ज़िलों के 386 स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को 1 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि राजस्थान महिला निधि से ऋण के रूप में प्रदान की। उन्होंने सामुदायिक स्तर पर विशिष्ट कार्य करने के लिये राजीविका कम्यूनिटी कैडर की 8 महिलाओं को भी पुरस्कृत किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2022-23 में महिला निधि की स्थापना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से करने की घोषणा की गई थी। तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है, जहाँ महिला निधि की स्थापना की गई है।
- महिला स्वयं सहायता समूह को मज़बूत बनाने, बैंकों से ऋण दिलाने, गरीब, सम्पत्तिहीन और सीमान्त महिलाओं की आय बढ़ाने व कौशल विकास कर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये महिला निधि की स्थापना की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपए तक के ऋण 48 घंटे में व 40,000 रुपए से अधिक के ऋण 15 दिवस की समय-सीमा में आवेदित सदस्यों के समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे।
- वर्तमान में राज्य के 33 ज़िलों में 2 लाख 70 हज़ार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें 30 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 हज़ार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें लगभग 6 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। राज्य में कुल 36 लाख परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से राजस्थान महिला निधि से लाभ मिलेगा।
- कार्यक्रम में अमेजॉन के साथ उत्पादों के ऑनलाइन विक्रय के लिये एमओयू करार किया गया। इससे 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर सूचीबद्ध किया जाएगा और देश भर के लाखों अमेजॉन ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके द्वारा कारीगरों और बुनकर समुदाय को सशक्त बनाने व उन्हें अमेजॉन विक्रेता बनाकर डिजिटल समावेश हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना व पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया।
- इस मौके पर टीएसपी क्षेत्र के 5 ज़िलों में पूर्व में लागू 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' का दायरा बढ़ाकर इसे सभी ज़िलों में लागू कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत दूसरे बच्चे के जन्म पर कुल 6000 रुपए 5 किश्तों में दिये जाते हैं। अब इस योजना का लाभ 1 अप्रैल, 2022 से पूरे 33 ज़िले की महिलाओं को मिल सकेगा।
- इसके अलावा कार्यक्रम में 'उड़ान योजना'के द्वितीय चरण का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख किशोरियों एवं महिलाओं के लिये 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के प्रथम चरण से 29 लाख किशोरियाँ और महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।

केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर में 4 नई सुविधाओं का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

28 अगस्त, 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत 60 वर्षों से ज़्यादा समय से उत्कृष्ट सेवाएँ दे रहे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) में एक साथ 4 नई सुविधाओं का उद्घाटन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने काजरी में बने नए सभागार, कृषि-व्यवसाय अभिपोषण केंद्र, पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र तथा इंडोर खेल हॉल का उद्घाटन किया।
- उन्होंने कहा कि काजरी द्वारा किये गए अनुसंधान कार्यों की वजह से टिब्बा स्थिरीकरण, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली से तथा फसलों, घासों व फलों की नई किस्मों के चलते कृषि में लागत कम होने से किसानों की आमदनी बढ़ रही है। काजरी द्वारा सौर ऊर्जा, खेती की लागत में कमी करने, पशुधन प्रबंधन जैसे कार्य भी शुष्क क्षेत्र के किसानों की लिये लाभदायक होंगे।
- काजरी के द्वारा समय-समय पर विकसित की जा रही नई तकनीकियों एवं शोध उपलब्धियों के कारण पिछले छः वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 8 पुरस्कार काजरी को मिले।
- गौरतलब है कि भूमि की तीव्रता से अवह्रास एवं उत्पादकता में कमी की प्रक्रिया को कम करने एवं संसाधनों के वैज्ञानिक तथा स्थाई प्रबंधन हेतु 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई थी, जिसका बाद में विस्तार 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ। अंततः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) के रूप में 1959 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया।
- काजरी जोधपुर स्थित मुख्यालय में 6 संभाग हैं। इसके चार क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र विभिन्न कृषि-जलवायु स्थितियों में स्थानाधारित समस्यानुगत अनुसंधान हेतु स्थित हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 का राज्यस्तरीय शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

29 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में खेलों के महाकुंभ के रूप में पहली बार आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 का राज्यस्तरीय शुभारंभ जोधपुर की लूणी पंचायत समिति के गाँव पाल से किया।

प्रमुख बिंदु

- राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों के विकास व खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज़ पर शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की सहभागिता तय करते हुए शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की महत्त्वाकांक्षी घोषणा की।
- इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक खेलों को हर वर्ष आयोजित करने की भी घोषणा की, ताकि ग्रामीण अंचल में खेलों के प्रति रुचि बनी रहे एवं अभ्यास का दौर निरंतर चलता रहे।
- उन्होंने कहा कि इन खेलों में प्रदेश की कुल 11 हज़ार 285 ग्राम पंचायतों में एक साथ लगभग 29 लाख 80 हज़ार खिलाड़ियों ने छह खेलों के लिये पंजीकरण कराया है। इनकी 2 लाख 21 हज़ार 55 टीमें बनी हैं, जिनमें 20 लाख 37 हज़ार पुरुष तथा 10 लाख महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं।
- राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी के लिये बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज होने पर इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया।

इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना

चर्चा में क्यों ?

30 अगस्त, 2022 को जोधपुर के श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति तक रोज़गार के अवसर पहुँचाने के लिये 'इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना'की शुरूआत 9 सितंबर, 2022 से करने की घोषणा की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना'की तर्ज़ पर राज्य में 'इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना'लागू करने की अभिनव पहल की गई है। अब तक इस योजना में लगभग 1.5 लाख लोगों द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है।
- मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर, असहाय एवं बेरोज़गार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज़ पर 'इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना'लागू की जा रही है।
- इस योजना का उददेश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार को एक वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोज़गार उपलब्ध करवाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवनयापन करने में मदद मिलेगी।
- यह देश में सबसे बड़ी शहरी रोज़गार गारंटी योजना है। योजना के लिये सालाना 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- योजना के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। आवेदक जिस वार्ड या ज़ोन में रहता है, उसे वहीं रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट :